



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

No. 354]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2005/श्रावण 26, 1927

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2005/SRAVANA 26, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2005

सं. 32/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 537(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम (सं. 2), 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और 93 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों के तथा पांडिचेरी और अंडमान निकोबार केन्द्रीय शासित क्षेत्रों के सुनामी प्रभावित जिलों (इसके पश्चात् उक्त क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित) में मकानों के निर्माण के लिए प्रयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 25 में आने वाली सीमेंट और अध्याय 72 या 73 में आने वाले स्टील (इसके पश्चात् उक्त माल के रूप में उल्लिखित), पर उक्त अधिनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क (इसके पश्चात् उक्त शुल्क के रूप में उल्लिखित)।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट केवल तभी लागू होगी यदि उक्त माल का उपयोग संबंधित राज्य अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकार द्वारा मकानों के निर्माण के लिए अनुमोदित गैर-सरकारी संगठन अथवा स्वयं सेवी अभिकरण अथवा निजी सार्वजनिक उद्यम अथवा पुनर्वास संगठन अथवा न्यास अथवा अन्य अभिकरण (इसके उपरांत अनुमोदित निर्माण अभिकरण के रूप में उल्लिखित), द्वारा उक्त क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य हेतु अस्थायी आश्रय स्थलों सहित मकानों के निर्माण (इसके उपरांत ऐसे मकान के रूप में उल्लिखित) हेतु किया जाता है।

3. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट निम्नलिखित रीति से प्रभावी होगी; अर्थात् :—

- (क) उक्त माल का निर्माता निकासी के समय उद्ग्रहणीय शुल्क अदा करेगा और उक्त शुल्क के प्रत्यर्पण के लिए योग्य नहीं होगा;
- (ख) अनुमोदित निर्माण अभिकरण ऐसे मकानों के निर्माण में प्रयुक्त उक्त माल की मात्रा और मूल्य का विवरण, और उक्त माल पर संदत्त शुल्क का साक्ष्य देने वाले दस्तावेजों सहित, उस अधिकार क्षेत्र के सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथास्थिति, (इसमें इसके पश्चात् क्षेत्राधिकारिक उत्पाद शुल्क अधिकारों के रूप में उल्लिखित) जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्मित किए जा रहे ऐसे मकान स्थित हैं, को प्रस्तुत करेगा।
- (ग) अनुमोदित निर्माण अभिकरण, संबंधित जिला अधिकारी या उप मंडल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किसी अधिकार पत्रित इंजीनियर द्वारा उक्त माल के उपभोग का प्रमाणपत्र और जिलाधीश द्वारा समापन प्रमाणपत्र के साथ ऐसे मकान के निर्माण के लिए प्राप्त किए गए और प्रयुक्त उक्त माल पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रत्यर्पण का दावा, क्षेत्राधिकारिक उत्पाद शुल्क अधिकारी को त्रैमासिक आधार पर, संबंधित तिमाही के समाप्ति के 60 दिन के भीतर पेश करेगा और इस अवधि को क्षेत्राधिकारिक उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा अगले 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है :

परंतु कि अप्रैल, 2005 से जून, 2005 की अवधि के प्रत्यर्पण का दावा 30 सितम्बर, 2005 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

- (ख) क्षेत्राधिकारिक उत्पाद शुल्क अधिकारी, स्वयं इस बात पर संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त माल का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया है और उक्त माल पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर, ऐसे मकान अथवा मकानों के निर्माण में आई लागत के 6 प्रतिशत के दर से प्रत्यर्पण स्वीकृत करेगा परंतु जिसकी अधिकतम राशि किसी भी मामले में 9 हजार रुपए प्रत्येक निर्मित हाऊस से अधिक नहीं होगी; तथा
- (ड) खण्ड (ध) में प्रत्यर्पण केवल संबंधित अनुमोदित निर्माण अभिकरण को ही किया जाएगा।

4. प्रत्यर्पण की राशि किसी भी मामले में ऐसे मकानों को बनाने में आयी लागत के 6 प्रतिशत या 9 हजार रुपए प्रत्येक निर्मित मकान, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

5. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट केवल उस माल पर संदत उक्त शुल्कों के संबंध में ही लागू होगी जिनका उपयोग उन मकानों में किया गया है जिनका निर्माण 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् तथा 31 जुलाई, 2006 को अथवा इससे पहले किया गया है।

[फा. सं. 341/2/2005-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2005

No. 32/2005-CENTRAL EXCISE

**G.S.R. 537(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with Section 91 and Section 93 of the Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts cement falling under Chapter 25, and steel falling under Chapters 72 or 73 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as said goods) used in construction of houses, in tsunami affected districts of States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Union Territories of Pondicherry and Andaman and Nicobar Islands (hereinafter referred to as said areas), from the whole of the duty of excise leviable thereon under the said Acts (hereinafter referred to as the said duties).

2. The exemption contained in this notification shall apply only if the said goods are used in construction of houses, including temporary shelters (hereinafter referred to as such houses) by Non-Government Organization or Voluntary Agency or Private-Public Enterprise or Rehabilitation Organization or Trust or any agency, approved by the concerned State or Union Territory Government (hereinafter referred to as approved construction agencies), for constructing such houses in the said areas, for rehabilitation work.

3. The exemption contained in this notification shall be given effect to in the following manner :—

- The manufacturer of the said goods shall pay duties as applicable at the time of clearance and shall not be eligible for the refund of said duties;
- The approved construction agency shall submit a statement of quantity and value of the said goods used in construction of such houses along with documents evidencing payment of duty on the said goods to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, (hereinafter referred to as jurisdictional excise officer), in whose jurisdiction the area where such houses are being constructed is situated;
- The approved construction agency shall file a claim for refund of the said duties paid on the said goods procured and utilized in construction of such houses by it on a quarterly basis, along with a consumption certificate for the said goods from a Chartered Engineer countersigned by the concerned District collector or Sub-Divisional Magistrate and completion certificate from the District Collector to the jurisdictional excise officer, within sixty days from the end of the relevant quarter, and such period may be extended by the jurisdictional excise officer by another sixty days :  
Provided that refund claim for the period April, 2005 to June, 2005 may be filed by the 30th September, 2005.
- The jurisdictional excise officer shall, after satisfying himself that the said goods have been used for the specified purposes, and on production of documentary evidence about the duty paid on the said goods, sanction the refund claim, at the rate of 6% of the cost of construction of such house or houses, as the case may be, subject to a maximum of Rs. 9000 per house constructed in any case; and
- The refund under clause (d) shall be given only to the concerned approved construction agency.

4. The amount of refund shall not exceed 6% of the cost of construction or Rs. 9000 per house constructed, whichever is less, in any case.

5. The exemption contained in this notification shall only be in respect of said duties paid on the said goods, which have been used in such houses constructed on or after the 1st April, 2005 and on or before 31st July, 2006.

[F. No. 341/2/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.